DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

पंजाब केसरी
DELHI
OF NEWSPAPERS
30 मार्च, 2023
DATED

डीडीए का 7643 करोड़ का बजट पारित

# विकास पर खर्च होंगे 3314 करोड़

**नई दिल्ली,** (पंजाब केसरी): दिल्ली के उपराज्यपाल व दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के अध्यक्ष वीके सक्सेना के अध्यक्षता में बुधवार को हुई अथॉरिटी मीटिंग में 2023-24 के लिए डीडीए के बजट को मंजूरी दी गई। इस दौरान विशेष रूप से नरेला, द्वारका और रोहिणी के सिविक इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने सहित कई बड़े फैसले लिए गए।

**नरेला, द्वारका व रोहिणी में सड़क-सीवेज पर विशेष ध्यान**

डीडीए ने 2023-24 के लिए 7643 बजट रखा जबकि डीडीए की कमाई 8541 करोड़ होने का अनुमान है। इनमें से 3314 करोड़ लैंड डेवलपमेंट, भौतिक बुनियादी ढांचे और मौजूदा बुनियादी ढांचे के रखरखाव के लिए खर्च किए जाएंगे जिसमें सड़कें, सीवेज, पानी की आपूर्ति, बिजली की लाइनें और जल निकासी शामिल हैं। ये क्षेत्र मुख्य रूप से नरेला, द्वारका और रोहिणी में हैं।

## अर्बन एक्सटेंशन रोड पर खर्च होंगे 3600 करोड़

एनएचएआई के माध्यम से दिल्ली की तीसरे रिंग रोड के रूप में अर्बन एक्सटेंशन रोड-II का निर्माण प्रगति पर है। इस परियोजना के लिए डीडीए द्वारा दिल्ली के हिस्से के लिए 3600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं इस प्रोजेक्ट पर कुल 6421 करोड़ रुपए का लागत आएगी। इस प्रोजेक्ट से दिल्ली की भीड़भाड़ कम करने में मदद मिलेगी जिससे वाहनों के प्रदूषण को कम करने से बहुत प्रभाव पड़ेगा। यह गुरुग्राम और सोनीपत के बीच सेंट्रल दिल्ली से गुजरने वाले ट्रैफिक को भी अनुमति देगा। इससे एयरपोर्ट तक तेजी से पहुंच भी बढ़ेगी। यह दिल्ली में एक अतिरिक्त पश्चिमी रिंग रोड के रूप में कार्य करेगा जिससे मुकरबा चौक से सिंघू बॉर्डर के बीच सड़क नेटवर्क को भीड़भाड़ मुक्त करेगा।

## भारत वंदना पार्क के लिए 105 करोड़

इन दिनों दिल्ली में प्रतिष्ठित भारत वंदना पार्क का निर्माण जोरों पर है। यह पार्क द्वारका स्थित सेक्टर-20 में 189.28 एकड़ में 524 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। इस साल डीडीए ने इसके लिए 105 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। यह पार्क दिल्ली में लोगों के आकर्षण का विशेष केन्द्र बनेगा।

## वाटर बॉडीज के लिए 55 करोड़

डीडीए ने दिल्ली में वाटर बॉडीज के कायाकल्प के लिए एक वर्क प्लान तैयार किया है। डीडीए ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में इसके लिए 55 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। जल निकायों की सिंचाई और कायाकल्प के लिए और पार्कों की सिंचाई के लिए ताजे जल स्रोतों पर निर्भरता कम करने के लिए डीडीए ने चार करोड़ का प्रावधान किया है।

## कठपुतली कॉलोनी प्रोजेक्ट के लिए 70 करोड़

डीडीए झुग्गीवासियों के यथास्थान पुनर्वास के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए 10 नई परियोजनाओं के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) मंगाई गई है। जेलरवाला बाग प्रोजेक्ट का डिजाइन और बिल्ड मॉडल पर 1675 ईडब्ल्यूएस निर्माण के अग्रिम चरण में हैं और 2023-24 के दौरान पूरा होने की संभावना है और कठपुतली कॉलोनी में 2800 ईडब्ल्यूएस फ्लैट पीपीपी मॉडल पर बन रहे हैं। इस पर डीडीए ने बजट में 70 करोड़ रुपए रखे हैं। जबकि 2023-24 में घरों के निर्माण के लिए कुल 1767 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है, इसमें से 240 करोड़ कड़कड़डूमा में टीओडी आधार पर बन रहे घरों के निर्माण पर खर्च किए जाएंगे।

## भूकंप रोधी बनेंगे नेहरू प्लेस

डीडीए द्वारा नेहरू प्लेस और भीकाजी कामा प्लेस वाणिज्यिक केन्द्रों को भूकंप रोधी बनाने के लिए रेट्रोफिटिंग और अपग्रेडेशन का कार्य किया जा रहा है। यहां मल्टीलेवल कार पार्किंग के निर्माण सहित कई नवीनीकरण के कार्य प्रगति पर हैं। इसके लिए बजट 2023-24 में 65 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

## यमुना बाढ़ मैदानों का कायाकल्प

दिल्ली में यमुना के बाढ़ मैदानों के कायाकल्प और जीर्णोद्धार के एलजी के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए डीडीए ने 928.28 करोड़ की धनराशि तय की है। यह काम 10 अलग-अलग छोटी परियोजनाओं के रूप में चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। 2023-24 में इस काम के लिए 405 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

## मेट्रो के चौथे चरण के लिए दिए 1000 करोड़

दिल्ली में मेट्रो नेटवर्क बढ़ाने के लिए डीडीए भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य से डीडीए ने दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान किया है।

**DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY**
**LIBRARY**
**PRESS CLIPPING SERVICE**

NAME OF NEWSPAPERS अमर उजाला ----------DATED----------

नई दिल्ली | बृहस्पतिवार, 30 मार्च 2023

# सब सिटी से तेज होगी विकास की रफ्तार

नई दिल्ली। नरेला, द्वारका और रोहिणी सब सिटी के विकास के लिए बुनियादी सुविधाओं को और सुदृढ़ बनाने की कवायद तेज हो गई है। मेट्रो, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में सुधार सहित दिल्ली को तीसरे रिंग रोड की तरफ डीडीए के बढ़ते कदम से विकास की रफ्तार बढ़ेगी।

नरेला-रोहिणी-द्वारका से गुजरने वाली यूईआर-2 (तीसरा रिंग रोड) से सोनीपत से गुरुग्राम जाने के लिए वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने की जरूरत नहीं होगी। दूसरे शहरों से एयरपोर्ट तक पहुंचने में भी काफी **कम** वक्त लगेगा। बुनियादी ढांचे में तेजी से होने वाले बदलाव से फ्लैटों की मांग भी और बढ़ेगी। फिलहाल, इन क्षेत्रों में माकूल बुनियादी सुविधाएं नहीं होने की वजह से फ्लैटों की मांग कम है। मेट्रो



फेज-4 के प्रस्तावित कॉरिडोर के निर्माण से भी सब सिटी का विस्तार और तेजी से होगा। हालांकि, तीन कॉरिडोर पर मंजूरी मिलने का इंतजार है। तीसरे रिंग रोड (यूईआर-2) के बनने से दिल्ली में वाहनों का बोझ काफी कम हो जाएगा।

इससे मुकरबा चौक से सिंघु बॉर्डर तक ट्रैफिक जाम की समस्या भी काफी कम होने की उम्मीद है। बजट में यूईआर-2 और रोहिणी, फेज-4 व 5, टीकरी कलां और नरेला के लिए सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में सुधार के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) को भी मंजूरी दी गई है। बसों के लिए सुविधाएं बढ़ने से यात्रियों को आवागमन में दिक्कत नहीं होगी। तीसरे रिंग रोड के रूप में अर्बन एक्सटेंशन रोड-2 (यूईआर-II) का निर्माण एनएचएआई के माध्यम से आगे बढ़ रहा है।

इस परियोजना लागत में से डीडीए की तरफ से 3600 करोड़ रुपये की राशि (दिल्ली क्षेत्र के लिए) प्रदान की गई है। यह रोड रोहिणी और नरेला के लिए महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी प्रदान करने के अलावा दिल्ली के लैंड पूलिंग क्षेत्रों के लिए भी सहायक होगी। बुनियादी सुविधाएं फिलहाल मजबूत नहीं होने से फ्लैटों की मांग कम है। ब्यूरो

30 मार्च • 2023 राष्ट्रीय सहारा

# जनसुविधाओं, यमुना के मुहानों को विकसित करने पर फोकस

■ नई दिल्ली (एसएनबी)।

उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बुधवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के वित्त वर्ष 2023-24 के बजट पर मुहर लगा दी। बजट में नागरिक सुविधाओं, यमुना नदी के मुहानों को विकसित के साथ ही लंबित योजनाओं पर विशेष फोकस किया गया है। बजट में राजधानी की निर्माणाधीन तीसरी रिंग रोड के रूप में अर्बन एक्सटेंशन रोड (यूईआर) के निर्माण के लिए 3,600 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया जाएगा।

वर्ष 2023-24 के लिए 7,643 करोड़ रुपए के खर्च के प्रावधान के साथ ही 8,541 करोड़ के राजस्व का लक्ष्य रखा गया है। बैठक में उपाध्यक्ष सुभाशीष पांडा, सदस्य विजेंद्र गुप्ता, सोमनाथ भारती, ओपी शर्मा, दिलीप कुमार पाण्डेय समेत प्राधिकरण के अन्य अधिकारी मौजूद थे। डीडीए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के विस्तार के लिए विशेष कदम उठाएगा। दिल्ली मेट्रो के लिए कुल 1000 करोड़ रुपए में से वर्ष 2023-24 के लिए 350 करोड़ रुपए प्रावधान किया गया है।

बजट पर चर्चा करते हुए डीडीए अध्यक्ष ने कहा कि वह इन-सीटू पुनर्वास योजना के तहत सभी स्लम बस्तियों के पुनर्वास के लिए प्रतिबद्ध हैं। रोहिणी और नरेला में स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स, द्वारका में गोल्फकोर्स का प्रस्ताव है। प्राधिकरण जंगपुरा में आरआरटीएस के लिए भूमि का भू-उपयोग परिवर्तित कर दिया गया है। नागरिक सुविधाओं का ध्यान रखते हुए प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र वाले इलाकों में रखरखाव, रोड, सीवेज, जल आपूर्ति, पावर लाइन, ड्रेनेज प्रणाली को विकसित करने के लिए बजट में 3,314 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। यह क्षेत्र प्रमुख रूप से नरेला, द्वारका, रोहिणी के हैं।

यमुना नदी के मुहानों को विकसित करने के लिए विस्तृत योजना तैयार की गई है। इसमें तीसरी रिंग रोड भी शामिल है। इस पर कुल परियोजना 6421 करोड़ रुपए की है। इसमें 3,600 करोड़ रुपए की राशि (दिल्ली के हिस्से) के लिए डीडीए को दी गई है। इस परियोजना के पूरे होने से रोहिणी एवं नरेला के लिए बेहतर कनेक्टिविटी होगी और डीडीए की लैंड पूलिंग योजना को मजबूती मिलेगी। दिल्ली से गुरु ग्राम एवं सोनीपत के बीच यातायात में व्यापक सुधार होगा। बजट में



रोहिणी के विकसित सेक्टर-20, 21, 22 एवं अविकसित सेक्टर-39, 40 एवं 41 की खाली पड़ी भूमि और इसके पास किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में 106 अनधिकृत कालोनियों में जल भराव को रोकने के लिए प्राधिकरण ने 293.21 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

**रेट्रोफिटिंग पर जोर :** डीडीए ने नेहरू प्लेस एवं भीकाजी कामा प्लेस स्थित व्यावसायिक सेंटरों की रेट्रोफिटिंग का काम शुरू कर दिया है। मल्टीलेवल कार पार्किंग के निर्माण समेत नवीनीकरण के लिए बजट में 65 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यमुना नदी के बाढ़ के मैदानों के पुनरुद्धार एवं कायाकल्प का काम शुरू हो गया है। 10 अलग-अलग योजनाओं के लिए बजट में 405 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। भारत वंदना पार्क का काम तेजी से चल रहा है। 524 करोड़ रुपए की यह परियोजना सेक्टर-

**डीडीए का बजट 2023-24**

- निर्माणाधीन तीसरी रिंग रोड को पूरा करने पर जोर
- मेट्रो के लिए 350 करोड़ रुपए आवंटित
- कड़कड़डूमा स्थित ईस्ट दिल्ली हब को विकसित करने के लिए दिया फंड
- इन-सीटू पुनर्वास योजना के तहत डीडीए स्लम बस्तियों के पुनर्वास के लिए प्रतिबद्ध : एलजी

20 द्वारका में 189.28 एकड़ में फैली हुई है।

**हरित क्षेत्र को बढ़ावा :** शहर में हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा पार्कों के साथ-साथ नए पार्कों को विकसित करने के लिए 61 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा डीडीए के करीब 787 पार्कों के रख-रखाव के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।

**आवासीय परिसरों से मिलने वाला राजस्व :** डीडीए ने मौजूदा आवासीय परियोजनाओं के अलावा इंवेंट्री की बिक्री से से करीब 4,310 रुपए का राजस्व मिलने का अनुमान है। द्वारका में आवासीय परियोजना में गोल्फ कोर्स के सामने करीब 1114 एचआईजी फ्लैट, लोक नायक पुरम में करीब 650 एमआईजी फ्लैट और नरेला में करीब 9000 एचआईजी/एमआईजी फ्लैट बनाने की योजना है।

**कड़कड़डूमा प्रोजेक्ट पर जोर :** बजट में दिल्ली में ट्रांजिट ओरिएंटिड डेवलपमेंट (टीओडी) मानदंडों पर आधारित आवासीय परिसरों का निर्माण प्रगति पर है। टीओडी में मेट्रो स्टेशनों, आवासों, कार्यस्थलों और मनोरंजनात्मक स्थलों को एक साथ लाना शामिल है। इस योजना के पहले चरण के लिए 1108 एमआईजी और 522 ईडब्ल्यूएस फ्लैटों का निर्माण कार्य शामिल है। आवासों के निर्माण के लिए 1,767 करोड़ रुपए का कुल प्रावधान किया गया है। इसमें 240 करोड़ टीओडी के आधार पर कड़कड़डूमा के आवासों के लिए निर्माण के लिए आवंटित किए गए हैं।

**DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY**
**LIBRARY**
**PRESS CLIPPING SERVICE**

NAME OF NEWSPAPERS----------DATED----------

the pioneer

| THURSDAY | MARCH 30, 2023

# ₹7,643 cr DDA budget gets LG nod

## ₹1,000 crore committed by authority for Metro Phase IV

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

Delhi Lieutenant-Governor (LG) VK Saxena on Wednesday approved the annual budget of the DDA for 2023-2024, with an annual outlay of ₹7,643 crore, focusing on civic infrastructure, particularly on the third Ring Road under the Urban Extension Road II (UER-II) for development of Narela, Dwarka and Rohini, rejuvenation and restoration of Yamuna floodplains and green spaces.

The DDA also approved Pre-Determined rates for Rohini, Phase IV and V, Tikri Kalan and Narela for financial year 2022-23 and permitted land use change for improving public transport system in Delhi. The budget has projected receipts to the tune of ₹8,541 crore.

As per the budget document, construction of UER-II as third Ring Road of Delhi is in progress through the National Highway Authority of India (NHAI). For this project, ₹3,600 crore will be funded by DDA out of the total project cost of ₹6,421 crore (for Delhi portion). This project will decongest Delhi and reduce vehicular pollution.

"It will also serve the land pooling areas of Delhi, apart from being an arterial connectivity to Rohini and Narela.. It will allow traffic moving between Gurugram and Sonepat to by-pass Central Delhi. This will also lead to faster access to the airport. It shall act as an additional Western Ring Road in Delhi, thereby decongesting the road network between Mukarba Chowk to Singhu Border," the budget document said.

The DDA has committed ₹1,000 crore for Phase IV of Delhi Metro and a provision of ₹350 crore has been made in BE 2023-24.

A total allocation of ₹3,314 crore has been made for development of land, physical infrastructure and maintenance of existing infrastructure that includes roads, sewage, water supply, power lines and drainage in development areas falling under the jurisdiction of DDA. These areas are primarily in Narela, Dwarka and Rohini. To contain encroachment of DDA's land, a provision of around ₹106 crore has been made towards security of land. The authority meeting was attended by Subhasish Panda, Vice-Chairman, DDA and other members including MLAs Vijender Gupta, Somnath Bharti, OP Sharma and DK Pandey.

The authority has planned construction of a Trunk Drain of about 7.2 Kms length, costing ₹293.21 crore to prevent waterlogging in DDA-developed sectors 20, 21 & 22, vacant land of undeveloped Sectors 39,40 and 41 of Rohini and adjoining 106 unauthorized colonies in Kirari Assembly constituency. A provision of ₹100 crore in BE 2023-24 has been kept for this purpose. Construction of Storm Water Drain at Sector-8, Dwarka is in progress. This drain will cater to the excess discharge of rain water of airport and prevent flooding in Rajnagar, Baghdola and Palam area. For this purpose, a provision of ₹30 crore has been made in 2023-24.

DDA, with an overall outlay of ₹928.92 crore, has undertaken the work of rejuvenation and restoration of the floodplains of river Yamuna. The work is being taken up in a phased manner as 10 separate sub-projects.

A sum of ₹405 crore has been provided in BE 2023-24 for this purpose. The construction of Bharat Vandana Park is in full swing. The park located in Sector-20, Dwarka, is spread over 189.28 acres with the project cost of ₹524 crore. A provision of ₹105 Crore has been kept in BE 2023-24 for this purpose.

DDA has projected revenue of around ₹4310 crore on account of sale of additional inventory of existing housing projects which are nearing completion. The housing projects that will be completed in the current year include projects in Dwarka having around 1114 HIG flats facing Dwarka Golf Course, around 650 MIG flats in Lok Nayak Puram and around 9000 HIG/MIG flats in Narela.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
CLIPPING SERVICE

the pioneer
NEW DELHI | THURSDAY | MARCH 30, 2023

DATED

# MCD budget with workers, traders at its core cleared

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

The much-awaited civic budget was cleared during a special meeting held at the Municipal Corporation of Delhi (MCD) on Wednesday, with the ruling AAP saying that "welfare of workers" is at the core of it. According to the MCD, the revised budget estimates for 2022-22 stand at ₹14,80,429 lakh (expenditure), while the budget estimate for 2023-24 stands at ₹16,02,355 lakh (expenditure).

AAP MLA and party's MCD in-charge Durgesh Pathak at a Press conference held after the end of the session at the Civic Centre, said the budget was cleared, and four resolutions introduced by its councillors for the welfare of traders were "also passed". The civic budget is worth ₹16,023 crore and puts focus on areas such as sanitation, education and health, a senior official said.

A piece of land measuring 47.346 acres has been allocated by the Delhi Development Authority (DDA) for a landfill site in Tehkhand area near Okhla, out of which 32.346 acres will be used for setting up an engineering landfill site, work for which is expected to be completed by April 2023, according to the budget speech of the Commissioner, made last December. Delhi has three sanitary landfill sites located at Ghazipur, Okhla and Bhalswa. This proposed "engineering landfill site" will be city's first such site, officials said.

MCD Mayor Shelly Oberoi presides over a special budget meeting of the Municipal Corporation of Delhi (MCD) house at the Civic Centre in New Delhi on Wednesday
Ranjan Dimri | Pioneer

The current three landfill sites in Delhi are spread over an area of 202 acres in total, according to the speech. In the budget, the Commissioner also said that CCTV cameras have been installed at 570 school locations, and proposals have been sent for other schools. Also, 1.5 lakh plants along with flower pots are planned to be bought in view of the G20 meetings, the budget had added. After discussion, the budget was passed, Pathak told reporters, soon after the session was over. "The welfare of workers is at the core of the budget, and besides the budget being passed, four resolutions introduced by our councillors for the welfare of traders were also passed.

These resolutions were brought in with the intent to provide relief to traders who have been facing problems due to sealing and other issues. Work on 'vikas' (development) will be carried out along with the welfare of workers, employees," he said. Today, two of the promises made in "Arvind Kejriwal's 10 guarantees have been fulfilled", and slowly other guarantees would also be fulfilled, Pathak said.

The AAP councillor and Leader of House Mukesh Goel told reporters that with the passage of the budget, "employees and workers will get salary on time". Pathak on Monday had announced that their councillors will introduce four resolutions for the welfare of traders during the special meeting of the civic body to discuss its budget.

One of the resolutions would be brought by AAP councillors Parveen Kumar and Sunil Chaddha relating to presenting the MCD's side before the judicial committee appointed by the Supreme Court to look into the matter of sealing of local shopping centres, he had said.

Prem Chauhan and Devender Kumar will bring another resolution, which will propose that the traders who have received notices will not be penalised, he had said. The fourth resolution proposed that no notices, whatsoever, be sent to local shopping centres and commercial shopping centres, Pathak said.

**DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY**
**LIBRARY**
**PRESS CLIPPING SERVICE**

NAME OF NEWSPAPERS---------- DATED----------

millenniumpost
NEW DELHI | THURSDAY 30 MARCH 2023

# In DDA Budget, focus on civic infra, rejuvenation of Yamuna floodplains and green spaces

**OUR CORRESPONDENT**

NEW DELHI: The DDA on Wednesday approved its Budget with an annual outlay of Rs 7,643 crore saying its focus is on the Capital's civic infrastructure and rejuvenation and restoration of Yamuna floodplains and green spaces in the city.

The Delhi Development Authority has committed Rs 1,000 crore for the Phase-IV project of the Delhi Metro, with Rs 350 crore provisioned in the Budget estimate 2023-24, the urban body said in a statement.

The budget received the nod during a meeting of Authority — the highest decision-making body of the DDA — here, chaired by Delhi Lt Governor V K Saxena, who is also the chairperson of the DDA.

The body, concerned majorly with housing, took major decisions, "including approval of the annual budget 2023-24, with focus on civic infrastructure of the national capital, particularly Narela, Dwarka and Rohini," the statement said, adding the budget has a special emphasis on Urban Extension Road-II, or UER II.

"The Authority approved the annual budget for 2023-24, with an annual outlay of Rs 7,643 cr and receipts projected at Rs 85,41 cr," the DDA said.

A total allocation of Rs 3,314 crore has been made for the development of land, physical infrastructure, and maintenance of existing infrastructure such as roads, sewage, water supply, power lines, and drainage in areas falling under the jurisdiction of DDA. These areas are primarily in Narela, Dwarka, and Rohini, the statement said.

The DDA, with an overall outlay of Rs 928.92 cr, has undertaken the work of rejuvenation and restoration of the floodplains of Yamuna river. The work is being taken up in a phased manner as 10 separate sub-projects. A sum of Rs 405 crore has been provided in the budget for this purpose.

The construction of the 'Bharat Vandana Park' is in full swing. Being built at a cost of Rs 105 crore, the park located in Sector-20, Dwarka, is spread over 189.28 acres, officials said.

According to them, DDA has played a key role in the overall development and management of green spaces in the city and to continue this initiative, it is carrying out development, upgradation, and modernisation of existing as well as new parks. DDA, which has under its maintenance around 787 parks, has provisioned Rs 400 crore for their upkeep.

It has also prepared an action plan for rejuvenation of water bodies across Delhi with a provision of Rs 55 crore in the budget.

For irrigation and rejuvenation of water bodies and to reduce dependence on fresh water sources for watering of parks, the DDA has been following a sustainable water management practice by using treated water through STP pipeline from centralised STPs and through decentralised STPs installed nearby drains. A total of Rs 4 crore has been set aside for the whole exercise, officials said.

A provision of Rs 33 crore has been made in the budget for the development and maintenance of seven biodiversity parks spread over an area of about 3,000 acres in Delhi, managed in collaboration with Centre for Environmental Management of Degraded Ecosystems, University of Delhi.

To contain encroachment of DDA's land, a provision of around Rs 106 crore has been made towards land safety and security, the statement said.

The DDA said that construction of UER-II as the third ring road of Delhi is in progress through NHAI. For this project, Rs 3,600 crore will be funded by the DDA out of the total project cost of Rs 6,421 cr (for Delhi portion). The project will have a great impact on decongestion of Delhi and reduction in vehicular pollution, it said.

Construction of two foot-over bridges in Dwarka is in progress, and for it, a provision of Rs 6 crore has been made, the statement said.

दैनिक भास्कर

एकीकरण के बाद एमसीडी का पहला बजट

# आप के सभी प्रस्ताव पास, भाजपा के रद्द

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

एमसीडी के एकीकरण के बाद बुधवार को निगम का पहला बजट पेश हुआ। एलजी वीके सक्सेना की अध्यक्षता में बजट प्रस्तावों को पास कर दिया गया। वहीं, भाजपा पार्षदों की ओर से लाए गए सभी 11 प्रस्ताव रिजेक्ट कर दिए गए।

डीडीए ने नागरिक अवसंरचना, यमुना बाढ़ के मैदानों के कायाकल्प और राजधानी में हरित स्थलों के विकास पर ध्यान देने वाले बजट को मंजूरी दी। एलजी की अध्यक्षता में डीडीए की मीटिंग हुई। इस दौरान डीडीए का बजट पास किया गया। संदीप कपूर ने कहा कि गली-मोहल्लों में कुत्तों के स्टेलेराइजेशन की समस्या गंभीर है। बजट में चार साल पहले जो प्रावधान था, वही आज भी है, इसका मतलब इसमें बदलाव नहीं हुआ। दूसरी ओर, सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गायों के लिए गौशाला बनाएंगे और गाडियां खरीदेंगे।

**DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY**
**LIBRARY**
**PRESS CLIPPING SERVICE**

NAME OF NEWSPAPERS---------- DATED

THE HINDU Friday, March 31, 2023
DELHI

# DDA eyes over ₹4,000 crore revenue from its housing inventory

**The Hindu Bureau**
NEW DELHI

In its 2023-24 budget passed on Wednesday, the Delhi Development Authority (DDA) said it expects to earn ₹4,310 crore by selling additional inventory in its existing housing projects. A large chunk of this revenue is expected from Dwaraka, which has 1,114 Higher Income Group (HIG) flats nearing completion, a senior DDA official said.

The official said the urban body also aims to garner revenue from its inventory in Narela, which will likely be connected with the Urban Extension Road (UER)-II this year. The road will provide arterial connectivity to Narela and Rohini, the budget presented by the urban body noted.

The DDA's previous attempts to dispose of its housing inventory in Narela were unsuccessful, with the lack of connectivity in the area being a major concern for homebuyers.

Last year, *The Hindu* had reported that all the housing schemes launched by the DDA since 2014 had received poor response, with most of its inventory being unsold.

"Apart from the completion of the UER-II, which will solve the larger issue of connectivity, a notification about Narela being connected with the rest of the Delhi Metro network will likely be issued soon," said a senior DDA official.

पंजाब केसरी
DELHI
▶ 31 मार्च, 2023 ▶ शुक्रवार

# कूड़े के पहाड़ की आड़ में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण

**नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) :** राजधानी दिल्ली में कूड़े के पहाड़ की आड़ में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण किया जा रहा है। यह निर्माण गाजीपुर डेयरी फार्म स्थित बी ब्लॉक स्थित अवैध मस्जिद के पीछे चल रहा है। इस निर्माण के पीछे स्थानीय नेताओं और अधिकारियों के मिलीभगत बताया जा रहा है। अखण्ड भारत मोर्चा के अध्यक्ष संदीप आहूजा ने इस पर रोष व्यक्त किया है। उनका कहना है कि हजारों गज जमीन पर सैकड़ों बीम व दीवारें खड़ी कर दी गई है।

मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने इसकी शिकायत दिल्ली पुलिस, उपराज्यपाल, दिल्ली नगर निगम, डीडीए के अलावा अन्य संबंधित विभागों को की है। वहीं इस अवैध निर्माण का एक वीडियो विभाग के ट्विटर हैंडल पर भी शेयर किया गया है। इस शिकायत के बाद काम को तो रोक दिया गया, लेकिन भूमाफियों पर इसका कोई भय नहीं दिखा। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बीते 26 मार्च को खड़ी दीवार पर शटरिंग डालकर सरिया भी बांध दिया गया। वहीं संबंधित अधिकारी इस पूरे प्रकरण पर आंखें मूंदे हुए हैं। आहूजा ने कहा कि कार्रवाई न होता देख हमारे कार्यकर्ताओं ने फिर इसकी शिकायत 112 नंबर पर की, बावजूद बिल्डिंग मैटेरियल का आना लगातार जारी है।

आहूजा ने आशंका जताया है कि इस अवैध निर्माण में भूमाफिया ने प्रशासन को मोटा चढ़ावा चढ़ाया है। यही कारण है कि अब तक इस मामले में किसी के खिलाफ कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस पर विभाग के द्वारा एक्शन नहीं लिया जाता है तो उनके कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगी। इसके साथ ही आहूजा ने कहा कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही है, जिसकी शिकायत उन्होंने दिल्ली पुलिस से की है।

THE HINDU Thursday, March 30, 2023
DELHI

# DDA budget cleared; Yamuna floodplains, roads get major push

**The Hindu Bureau**
NEW DELHI

The Delhi Development Authority (DDA) on Wednesday passed its budget at a meeting chaired by Lieutenant-Governor Vinai Kumar Saxena, who also serves as its chairman. With a focus on civic infrastructure, development of green spaces and rejuvenation of the Yamuna floodplains, the 2023-24 DDA budget has an annual outlay of ₹7,643 crore and receipts projected at ₹8,541 crore.

The authority has set aside ₹3,314 crore for the development of land and maintenance of existing infrastructure in Narela, Dwarka and Rohini. For the construction of the Urban Extension Road-II as the third Ring Road, the DDA has allocated ₹3,600 crore. Other major ongoing infrastructure projects that received funds include retrofitting and upgradation of Nehru Place and Bhikaji Cama Place commercial centres, rejuvenation and restoration of the Yamuna floodplains as 10 separate sub-projects.

The urban body also aims to collect almost ₹4,310 crore through the sale of its inventory in existing housing projects that are nearing completion.

**DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY**
**LIBRARY**
**PRESS CLIPPING SERVICE**

NAME OF NEWSPAPER नई दिल्ली, 30 मार्च, 2023 दैनिक जागरण DATED----------

# बदरपुर सुभाष कैंप में ध्वस्त किए छह अवैध निर्माण, मची अफरातफरी

- एक सप्ताह पूर्व डीडीए ने नोटिस चस्पा किया, कार्रवाई के एक दिन पहले किया था अलर्ट
- बदरपुर सुभाष कैंप में सौ से अधिक स्थायी व अस्थायी अवैध निर्माण, कई घरों पर बिजली के मीटर भी लगे
- टीम के आने पर अवैध रूप से लगने वाले बाजार को हटा लेते हैं लोग, अगले दिन फिर से लगा लेते हैं

बदरपुर मे डीडीए द्वारा हटाया गया अतिक्रमण • जागरण

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली: एनटीपीसी के पास बदरपुर सुभाष कैंप में बुधवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। डीडीए ने अभियान चलाकर करीब आधा दर्जन से अधिक अस्थायी निर्माण को ध्वस्त किया। एक सप्ताह पहले डीडीए ने इस संबंध नोटिस चस्पा किया था। मंगलवार को टीम ने मौके पर जाकर लोगों को अलर्ट भी जारी किया था। इसके बावजूद जिन लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया था उनके खिलाफ बुधवार को डीडीए ने अभियान चलाकर कार्रवाई की। इस मामले में डीडीए का पक्ष जानने के लिए संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनका जवाब नहीं मिला।

**करीब 40 वर्षों से हो रहा है अतिक्रमण:** एनटीपीसी से सटा हुआ बदरपुर सुभाष कैंप में करीब सौ से अधिक स्थायी और अस्थायी अवैध निर्माण है। यहां डीडीए का एक तालाब भी है। इस तालाब के किनारे पूरा अतिक्रमण है। इस इलाके में करीब 40 वर्षों से अतिक्रमण हो रहा है। कई परिवारों की दूसरी पीढ़ी यहां रह रही है। इतना ही नहीं कई घरों में बिजली के मीटर भी लग गए हैं। स्थानीय निवासी पवन कुमार ने बताया कि हम कई वर्षों से बिजली का बिल दे रहे हैं। उनका यहां पक्का स्थायी मकान है। यहां के लोगों को अंदाजा नहीं था कि डीडीए यह कार्रवाई कर सकता है। स्थानीय निवासी सतबीर को इस बात की जानकारी है कि यह डीडीए की जमीन है, लेकिन वह इसको लेकर निश्चिंत थे कि डीडीए ने कभी उनके निर्माण पर आपत्ति नहीं की।

### रमजान माह में हुई परेशानी

स्थानीय निवासी अहमद ने बताया कि कई लोग 1996 से रह रहे हैं। उनके निर्माण को नहीं ध्वस्त किया गया। उन्होंने कहा कि यह समय हमारे रमजान का है। इस समय उनका परिवार फ्लाईओवर के नीचे शरण लिए हुए है। अहमद यह मानते हैं कि वह अवैध रूप से रह रहे है, लेकिन उनका कहना है कि हमें यहा से हटने का थोड़ा और मौका देना चाहिए। रमजान के बाद हम यहा से खुद चले जाते। स्थानीय निवासी सतवीर ने बताया कि डीडीए के तालाब के किनारे बड़ी मछली बाजार लगती है। अक्सर मछली बाजार को हटाने के लिए कई बार डीडीए की टीम यहा आती रही है। उस दौरान लोग बाजार हटा लेते हैं लेकिन दूसरे दिन फिर बाजार लगा लेते हैं। कभी डीडीए टीम ने यहा के निर्माण पर कोई आपत्ति नहीं की।

हिन्दुस्तान

# डीडीए बजट : मेट्रो के चौथे चरण और तीसरे रिंग रोड को देंगे रफ्तार

**नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता।** दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) बोर्ड की बैठक बुधवार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना की अध्यक्षता में हुई। इसमें 2023-24 के 7,643 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया गया है।

बजट में दिल्ली के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ हरित दिल्ली बनाने पर जोर दिया है। साथ ही तीसरे रिंग रोड के निर्माण, नरेला, द्वारका, रोहिणी का विकास, यमुना डूब क्षेत्र के पुर्नविकास और ईडब्ल्यूएस फ्लैट के निर्माण पर जोर रहेगा।

डीडीए ने भूमि के विकास, भौतिक बुनियादी ढांचे और मौजूदा बुनियादी ढांचे के रखरखाव के लिए 3314 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की है। इसमें सड़क, सीवेज, पानी की आपूर्ति, बिजली की लाइनें और जल निकासी शामिल हैं। इसका फायदा खासतौर से नरेला, द्वारका और रोहिणी क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। मेट्रो फेज चार के लिए 350 करोड़ की राशि और भूमि उपयोग बदलने की मंजूरी दी है। यमुना रिवर फ्रंट के व्यापक विकास की भी योजना बनाई है।

## 7643 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी मिली उपराज्यपाल की अध्यक्षता में, यमुना डूब क्षेत्र का होगा पुनर्विकास

**रिंग रोड :** डीडीए तीसरे रिंग रोड के रूप में अर्बन एक्सटेंशन रोड का निर्माण एनएचएआई के साथ कर रहा है। इसके लिए 3600 करोड रुपये डीडीए देगा। इससे रोहिणी और नरेला के साथ कनेक्टविटी बढ़ जाएगी।

**मकान :** कड़कड़डूमा, दिल्ली में पारगमन उन्मुख विकास (टीओडी) मानदंडो के आधार पर आवासीय परिसरो का निर्माण किया जाएगा। पहले चरण मे 1108 एमआईजी और 522 ईडब्ल्यूएस आवासीय फ्लैट बनेगे।

### खास बातें

- रोहिणी सेक्टर-20, 21, 22 और अविकसित सेक्टर- 39, 40 और 41 में पानी के जमाव को रोकने के लिए 293.21 करोड 7.2 किलोमीटर लबी ट्रक ड्रेन बनेगी
- नेहरू प्लेस और भीकाजी कामा प्लेस व्यवसायिक केंद्रो को अपग्रेड किया जाएगा। बहुमंजिला कार पार्किंग के निर्माण सहित नवीनीकरण का काम होगा
- यमुना के डूब क्षेत्र के कायाकल्प के लिए 10 परियोजनाओं पर 405 करोड़ रुपये होंगे
- द्वारका स्थित भारत वंदना पार्क के लिए 105 करोड का प्रावधान
- हरित स्थानो के समग्र विकास और प्रबधन के लिए 787 मौजूदा और नए पार्को के विकास के लिए 461 करोड रुपये का प्रावधान
- मेट्रो के चौथे चरण मे नरेला से बेहतर कनेक्टविटी के लिए 1000 करोड रुपये डीडीए को देने है। 350 करोड़ का प्रावधान किया
- द्वारका सेक्टर-आठ, 17, 19 और 23 खेल परिसार की शुरुआत इसी साल के अंत तक

**DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY**
**LIBRARY**
**PRESS CLIPPING SERVICE**

Hindustan Times NEW DELHI THURSDAY MARCH 30, 2023

# DDA budget focuses on housing projects

**HT Correspondent**
htreporters@hindustantimes.com

**NEW DELHI:** Upgrading civic infrastructure in the three subcities of Narela, Rohini and Dwarka, and completion of pending housing projects, are the key focus areas of the Delhi Development Authority's budget for the 2023-24 financial year.

According to the plan, which was approved by Delhi lieutenant governor (LG) VK Saxena on Wednesday, the agency proposes to complete the construction of close to 11,000 high- and middle-income group flats (HIG and MIG) in Dwarka, Lok Nayak Puram in west Delhi, and Narela.

The agency has decided to spend ₹3,314 crore on upgrading the civic infrastructure in its three sub-cities — Dwarka, Narela and Rohini — where it has a number of housing projects. While approving the budget, the LG, who is the DDA chairman, directed officials to ensure "visible implementation in a time-bound manner".

According to budget documents, the total outlay for the financial year 2023-24 is ₹7,643 crore, which is ₹290 crore less than the previous plan. DDA has put the projected receipts in the next financial year at ₹8,541 crore, which is about ₹600 crore more than the projected receipts for the 2022-23 fiscal.

While no new project has been announced in the budget, the focus this year is going to be on completing ongoing housing projects, said a senior DDA official.

The official said that 1,114 HIG flats facing the golf course in Dwarka Sector 24, nearly 650 MIG flats in Lok Nayak Puram, and about 9,000 HIG and MIG flats in Narela, will be ready this year.

Of the ₹1,767 crore for housing projects, ₹240 crore will be spent on construction of 1,108 MIG and 522 EWS flats in east Delhi's Karkardooma — a project touted as India's first Transit-Oriented Development project.

DDA has also set aside ₹70 crore for the 10 in-situ slum redevelopment projects. "DDA has projected a revenue of ₹4,310 crore on account of sale of additional inventory of existing housing projects which are nearing completion.

It is expected that completion of Urban Extension Road-II, connecting NH-48 to NH-2, Narela and the proposed Metro line, which is expected to be approved by government shortly, will give a fillip to the demand of DDA flats in Narela," the agency said in a statement.

Dwarka is also getting a major makeover with an expressway and a host of facilities such as the international convention centre, sports complexes and the Bharat Vandana Park.

Last year, DDA decided to pay ₹3,600 crore as viability gap funding to the National Highways Authority of India for the construction of Urban Extension Road -II, often referred to as the third Ring Road of Delhi.

The agency has set aside ₹405 crore for payments in the next fiscal.

## DDA's budget for FY 2023-24

**OUTLAY ₹7,643 crore**

- **₹8,541cr** Projected receipts
- **₹3,314cr** Total allocation for infrastructure projects

**Fund allocation to some important projects in this budget**

- **₹1,767cr** for flats, as part of DDA's TOD project
- **₹65cr** to retrofit and upgrade Nehru Place and Bhikaji Cama Place district centres
- **₹405 crore** for the rejuvenation of the riverfront (total cost is ₹928.92 crore)
- **₹350cr** for Phase IV of Delhi Metro
- **₹105cr** for ₹524 crore Bharat Vandana Park
- **₹155cr** for 5 new sports complexes in Dwarka
- **₹70cr** for in-situ slum redevelopment

**PROJECTS TO BE COMPLETED THIS YEAR**

- 1,114 High-Income Group (HIG) flats at Dwarka, 650 Middle-Income Group (MIG) flats in Lok Nayak Puram and around 9,000 HIG/MIG flats in Narela
- Sports complexes in Dwarka
- Bharat Vandana Park



THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI THURSDAY, MARCH 30, 2023

# Finally, shops at Barapullah exit to DND demolished

**Siddhanta.Mishra**
@timesgroup.com

**New Delhi:** There is some relief for motorists using the Barapullah elevated road to reach Noida. Many of the shops and stalls encroaching on the road space were removed by Delhi Development Authority on Tuesday.

Vehicles exiting the Barapullah corridor and going towards DND Flyway or Ashram and Maharani Bagh regularly ran into a traffic congestion caused by some furniture shops and shikanji and fruit stalls, where many cars parked and people got off to take a break. Due to this, the stretch was among the perennial bottlenecks on Ring Road. TOI had carried a news report on this congestion point in January.

Past the Sun Dial pedestrian bridge, where the Barapullah elevated road exited on Ring Road, motorists encounter a shrunken road width with shops taking up space on the left side of the road. The eroded road surface at this point also slowed down the vehicles. After exiting the Barapullah road, vehicles take a left turn towards DND to access the road to Noida.

On Wednesday, the shikanji shop located at the turn stood demolished as did the other shops. Some people could be seen picking up whatever could be retrieved from the rubble. The angry shop owners argued that DDA had no right to tear down their stalls because the land belonged not to the agency, but to a private individual.

"This land belongs to us, DDA has no jurisdiction over this land," insisted Gaurav Sharma, who claimed to be owner of the plot bearing the khasra number 520. "Moreover, we were not even given time to vacate the space. The officials came and pasted notices on the doors of the shops on Saturday evening and then carried out what they called an anti-encroachment drive on Tuesday."

There were no comments from DDA on **TOI**'s queries.

With the work of the Ashram flyover extension completed and the obstructing shops at this critical turn removed, traffic congestion on this stretch could be a thing of the past.

Anindya Chattopadhyay

DDA has taken action against several furniture, shikanji and fruit shops, which is likely to give relief to commuters heading towards DND

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---------- DATED---------- THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
THURSDAY, MARCH 30, 2023

# DDA earmarks ₹3k crore for infra plans, Yamuna floodplain in focus

Vibha.Sharma@timesgroup.com

**New Delhi:** The Delhi Development Authority (DDA) has allocated Rs 3,314 crore, which is a major chunk of its 2023-24 budget, to infrastructure projects such as facilities in three sub-cities of Narela, Dwarka and Rohini, and the Urban Extension of Roads II project.

The authority approved the budget in a meeting on Wednesday, chaired by Lieutenant Governor V K Saxena.

Rejuvenation and restoration of the Yamuna floodplains, green spaces, approval of pre-determined rates for Rohini Phase IV and V, Tikri Kalan and Narela for 2022-23 and permitted land use change for improving public transport system in Delhi are among the budget highlights.

Pre-determined rates are the rates chargeable for allotment of alternative land to different categories of persons whose plots have been acquired for planned development of Delhi.

Completing prominent housing projects to increase revenue generation was also emphasised in the budget.

"A total allocation of Rs 3,314 crore has been made for development of land... maintenance of existing infrastructure that includes roads, sewage, water supply, power lines and drainage primarily in Narela, Dwarka and Rohini," the budget said.

Among the projects targeted for completion this year are the 1,114 high-income group (HIG) flats at Dwarka, 650 MIG flats in Lok Nayak Puram and around 9,000 HIG/MIG flats in Narela.

The much-awaited sports complexes in Dwarka's Sector 17, 8, 19 and 23 and a golf course at Sector 24 are on the list of projects targeted to be over this year.

The completion of the Bharat Vandana Park is expected this year and Rs 105 crore has been allocated for the Rs 524-crore project.

"We are projecting revenue of around Rs 4,310 crore on account of sale of additional inventory of existing housing projects which are nearing completion. That's why emphasis has been given to complete all ongoing housing projects. Flats in Lok Nayak Puram and Narela are in close proximity to UER-II where the work is in full swing," said the official.

The authority is focused on undertaking retrofitting and upgrade of the Nehru Place and Bhikaji Cama Place Commercial Centres. "The refurbishment work, including construction of multi-level car parking, is in progress. A provision of Rs 65 crore has been made in BE 2023-24 for this purpose," said the official.

On the Yamuna Rejuvenation plan, the overall outlay is Rs 928.92 crore. "While work has been taken up in a phased manner as 10 separate sub-projects, a sum of Rs 405 crore has been provided in BE 2023-24 for this purpose," the budget said.

The DDA has also prepared an action plan for rejuvenation of water bodies across Delhi for Rs 55 crore. "For irrigation and rejuvenation of water bodies and to reduce dependence on fresh water sources for watering of parks, DDA has implemented sustainable water management practices. To continue with these techniques, a provision of Rs 4 crore has been kept in the budget estimate for 2023-24," the budget said.

A request for a proposal has been floated for 10 projects for in situ rehabilitation of slum dwellers while work on Jailorwala Bagh is targeted to be complete this year.

## THE HIGHLIGHTS

₹3,314 crore | Infrastructure projects at three sub-cities, including Narela, Dwarka and Rohini; completion of Urban Extension Road II

₹1,767 crore | Construction of flats, including ₹240 crore for flats at Karkardooma as part of DDA's transit-oriented development project

₹350 crore | Phase-IV of Delhi Metro under which connectivity to Narela is proposed

₹405 crore | Rejuvenation of riverfront project

**Financial budget for 2023-24 approved**

Annual outlay ₹7,643 crore

Receipts projected ₹8,541 crore

₹400 crore | Upkeep and development of green spaces

₹106 crore | Protect DDA land from encroachment

₹155 crore | Development of five sport complexes in Dwarka; ₹178 crore for maintenance of existing sports facilities

₹65 crore | Retrofitting and upgradation of Nehru Place and Bhikaji Cama Place district centres

₹ 100 crore | Improving drainage in Rohini, 106 unauthorised colonies in Kirari

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE



# सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बन रही थी मस्जिद, निर्माण रुकवाया

## गाजीपुर लैंडफिल साइट के पास अवैध निर्माण की मिली थी शिकायत

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली: गाजीपुर लैंडफिल के पास सरकारी जमीन पर अवैध रूप से मस्जिद बनाने का मामला सामने आया है। हिंदू अखंड भारत मोर्चा की शिकायत पर जिला प्रशासन ने इस निर्माण कार्य को रुकवा दिया है। प्रशासन की ओर से एसडीएम मयूर विहार ने मस्जिद का निर्माण कार्य कर रहे लोगों से जमीन के कागजात मांगे तो वह दिखा नहीं सके, न ही उनके पास निर्माण कार्य के लिए निगम की अनुमति थी। जमीन किस सरकारी विभाग की है स्पष्ट नहीं हो पाया है। एसडीएम ने डीडीए, नगर निगम व दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड को पत्र लिखकर जमीन के बारे में जानकारी मांगी है। फिलहाल निर्माण कार्य रुकवा दिया है।

गाजीपुर लैंडफिल साइट के पास सरकारी जमीन पर अवैध रूप से किया गया निर्माण • सौ. अखंड भारत मोर्चा

एसडीएम संदीप दत्ता ने बताया कि उन्हें एक शिकायत मिली थी कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने बिना देर किए निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। गाजीपुर थानाध्यक्ष को आदेश का पालन करवाने के लिए कहा है। निर्माण कार्य करने वाले जमीन के कागजात नहीं दिखा पा रहे हैं। डीडीए, निगम व शहरी आश्रय सुधार बोर्ड से पांच अप्रैल तक जमीन के स्वामित्व में जवाब मांगा है।

शिकायतकर्ता संगठन ने बताया लैंड जिहाद: हिंदू अखंड भारत मोर्चा ने अध्यक्ष संदीप आहुजा ने अवैध निर्माण को लैंड जिहाद बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भू-माफिया सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे पुलिस व अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने दिल्ली पुलिस, प्रशासन व उपराज्यपाल से मांग की है कि जो लोग सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए व जो धार्मिक स्थल को जितना हिस्सा बन गया है उसे ध्वस्त किया जाए। सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए।

# दिल्ली को 'महकाने' से पहले ही 'मुरझाने' लगे चंदन के पौधे

संजीव गुप्ता • नई दिल्ली

- उपराज्यपाल ने राजधानी में चंदन के 10 हजार पौधे लगाने के दिए थे निर्देश
- ज्यादातर जगह चंदन नहीं पकड़ पा रहा जड़, इसके चलते मुरझाने लगे हैं पौधे
- विशेषज्ञों के अनुसार दिल्ली की जलवायु और मिट्टी चंदन के पौधे के अनुकूल नहीं

इसे विडंबना कहें या अनदेखी... दिल्ली को 'महकाने' से पहले ही चंदन के पौधे 'मुरझाने' लगे हैं। इसकी मुख्य वजह राजधानी की मिट्टी और जलवायु का इनके अनुकूल न होना है। हालांकि जहां कहीं इनकी ठीक से देखभाल की जा रही है, वहां अपेक्षाकृत स्थिति कुछ बेहतर है।

गौरतलब है कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने गत जुलाई माह में एनडीएमसी, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण को मानसून के मौसम में शहरभर में चंदन के 10,000 पौधे लगाने का निर्देश दिया था। एनडीएमसी ने करीब एक हजार पौधों का रोपण किया। डीडीए की ओर से भी अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क में 500 पौधे लगाए गए जबकि यमुना व कमला नेहरू रिज बायोडायवर्सिटी पार्क में चंदन के बीज डालकर नर्सरी तैयार की गई। वहीं नगर निगम की ओर से चंदन के कहां और कितने पौधे लगाए गए, इसे लेकर कुछ स्पष्ट नहीं है।

### योजना पर पहले ही उठे थे सवाल

पर्यावरण विशेषज्ञ प्रदीप कृष्ण दिल्ली में चंदन के पौधे लगाने की योजना की सफलता पर पहले ही सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने कहा था, ''यदि आप एक ध्रुवीय भालू को दिल्ली में लाते हैं और उसे बर्फ के घर में रखते हैं, तो वह जीवित रह सकता है, लेकिन ऐसा करना मूर्खतापूर्ण होगा। इसी तरह पौधों के लिए मिट्टी, नमी और जलवायु अनुकूल रखने की जरूरत होती है। जिस वक्त आप पौधे की देखभाल करना बंद कर देंगे, वह सूख जाएगा।''

यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क में विशेष तौर पर बनाई गई नर्सरी में सूखे पड़े चंदन के ज्यादातर पौधे • जागरण

बताया जाता है कि अभी तक दिल्ली में चंदन के जितने भी पौधे रोपे गए हैं, उनमें एक बड़ी संख्या में पौधे सूख गए हैं। खासतौर पर नर्सरी में बीज डालकर रोपे गए पौधे 20 से 30 प्रतिशत संख्या में ही जीवित बचे हैं। एनडीएमसी में 10 से 20 प्रतिशत पौधों के सूख जाने की बात सामने आ रही है तो डीडीए द्वारा अरावली पार्क में रोपे गए पौधों में से भी अधिकांश की हालत बहुत संतोषजनक नहीं बताई जा रही।

नाम न छापने के अनुरोध पर डीडीए और वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली की जलवायु और यहां की मिट्टी चंदन के पौधों के लिए बहुत अनुकूल नहीं है। ऐसे में उन्हें बड़ा करने के लिए बहुत देख- भाल की जरूरत है।

### 12 से 15 साल में तैयार होता है चंदन का पेड़

चंदन का एक पेड़ 12 से 15 साल में तैयार होता है। मौजूदा दरों के अनुसार 12-15 लाख रुपये में बिकता है। इस दर पर 10,000 चंदन के पेड़ तैयार होंगे तो इनसे 12 से 15 हजार करोड़ रुपये मिलेंगे। उपराज्यपाल ने कहा था कि चंदन का पौधरोपण, राजधानी की वनस्पति विविधता को जोड़ने और सामान्य वातावरण को समृद्ध करने के अलावा, सरकारी भूमि से आमदनी को बढ़ावा भी देगा। भूमि देने वाली एजेंसियों और किसानों, भूमि-धारकों के लिए वित्तीय संपत्ति भी खड़ा करेगा। यही नहीं, ससाधन की कमी वाले किसान चंदन के दो पेड़ों से ही अपने बच्चों की शिक्षा पूरी कर सकते हैं।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

। नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । गुरुवार, 30 मार्च 2023

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2023 दैनिक जागरण PAPERS

# विकास की राह

**डीडीए की** बोर्ड बैठक में वर्ष 2023-24 के लिए 7,643 करोड़ रुपये का बजट पारित किया गया। बजट में दिल्ली के विकास, पर्यावरण और खेल सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। जी-20 सम्मेलन को देखते हुए दिल्ली को संवारने और सुंदर बनाने का भी फैसला किया गया है। बजट में किए गए प्रविधान से दिल्ली के विकास में तेजी आएगी। दिल्लीवासियों की समस्या भी दूर होगी। राजधानी विशेषकर नरेला, द्वारका व रोहिणी में नागरिक सुविधाओं को बेहतर करने के लिए आधारभूत ढांचे का विकास किया जाएगा। नरेला को उपनगरी के रूप में विकसित करने का काम चल रहा है। इस काम में तेजी लाने के लिए परिवहन व्यवस्था व अन्य सुविधाएं बढ़ाने की जरूरत है। बजट में इसे लेकर कदम उठाए गए हैं।

> यमुना के किनारों को अतिक्रमण मुक्त, साफ व सुंदर बनाना भी जरूरी है, इससे यमुना को स्वच्छ बनाने में मदद मिलेगी

झुग्गी बस्तियां दिल्ली को व्यवस्थित व सुंदर बनाने में बड़ी बाधा हैं। कई परियोजनाओं का काम इससे बाधित हो रहा है। इसे ध्यान में रखकर झुग्गीवासियों के पुनर्वास के लिए डीडीए काम कर रहा है। झुग्गीवासियों को पक्के मकान दिए जा रहे हैं। इस काम को आगे बढ़ाने के लिए बजट में विशेष प्रविधान किया गया है। यमुना के किनारों को अतिक्रमण मुक्त, साफ व सुंदर बनाना भी जरूरी है। इससे यमुना को स्वच्छ बनाने में मदद मिलेगी। कुल मिलाकर बजट में उठाए गए कदम सराहनीय हैं, लेकिन इसे जमीन पर उतारने के लिए गंभीरता से काम करने की जरूरत है। अक्सर घोषणाओं व वादों को पूरा करने को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई जाती है। परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करनी होगी।

# DDA बजट: इन्फ्रास्ट्रक्चर, साफ यमुना और ग्रीन स्पेस पर फोकस

## एलजी की अध्यक्षता में हुई बोर्ड मीटिंग में बजट को मंजूरी

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

**एलजी वी.** के. सक्सेना की अध्यक्षता में हुई डीडीए की बोर्ड मीटिंग में 2023-24 के वार्षिक बजट को मंजूरी दी गई। इस बार का डीडीए का बजट इन्फ्रास्ट्रक्चर, यमुना के जीर्णोधार और ग्रीन स्पेस के विकास की योजनाओं पर केंद्रित है। इसके अलावा नरेला, द्वारका और रोहिणी के विकास और दिल्ली की तीसरी रिंग रोड पर भी फोकस किया गया है। रोहिणी, फेज-4 और 5, टिकरी कलां और नरेला की पूर्व निर्धारित दरों को मंजूरी के साथ राजधानी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सुधार के लिए लैंड यूज में बदलाव को भी मंजूरी दी गई है।

डीडीए की बोर्ड मीटिंग में एलजी के अलावा डीडीए के वाइस चेयरमैन शुभाषीश पांडा, सदस्य विजेंद्र गुप्ता, सोमनाथ भारती, ओपी शर्मा, दिलीप कुमार पांडे भी मौजूद रहे। 2023-24 के लिए एनुअल आउटले 7643 करोड़ और रिसिप्ट प्रोजेक्ट के लिए 8541 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी गई है।

डीडीए की बोर्ड मीटिंग में 2023-24 के लिए एनुअल आउटले 7643 करोड़ और रिसिप्ट प्रोजेक्ट के लिए 8541 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी गई है

### इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ तीसरी रिंग रोड पर भी ध्यान

**3314** करोड़ का बजट तय किया गया है इस बार इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए

₹

**3600** करोड़ मिलेंगे दिल्ली की तीसरी रिंग रोड (UER-2) प्रोजेक्ट के लिए

### इन्फ्रास्ट्रक्चर पर किया गया है फोकस

इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 3314 करोड़ का बजट तय किया गया है। इस बजट से नरेला, द्वारका और रोहिणी में मौजूदा इन्फ्रास्ट्रक्चर की मेंटनेंस का काम होगा। दिल्ली की तीसरी रिंग रोड (यूईआर-2) का काम चल रहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए 3600 करोड़ का फंड मिलेगा। इससे राजधानी को जाम मुक्त करने में मदद मिलेगी। रोहिणी के विभिन्न सेक्टरों को जलभराव से राहत दिलाने के लिए 293.21 करोड़ से ट्रंक ड्रेन बनेगी। एयरपोर्ट पर जलभराव से राहत दिलाने के लिए 30 करोड़ रुपये स्ट्रॉम वॉटर ड्रेन निर्माण को दिए गए हैं। नेहरू प्लेस और भीकाजी कामा प्लेस कमर्शल सेंटर की मरम्मत और अपग्रेडेशन के साथ वहां मल्टीलेवल कार पार्किंग के लिए 65 करोड़ दिए गए हैं।

### यमुना बाढ़ क्षेत्र का होगा सौंदर्यीकरण

यमुना बाढ़ क्षेत्र के सौंदर्यीकरण के लिए इस साल 405 करोड़ दिए गए हैं। द्वारका में बन रहे भारत वंदना पार्क के लिए 105 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। पार्कों के रखरखाव के लिए 400 करोड़, झीलों को पुनर्जीवित करने के लिए 55 करोड़ और 7 बायोडायवर्सिटी पार्क के लिए 33 करोड़ रुपये मिलेंगे। दिल्ली मेट्रो फेज-4 के लिए 350 करोड़ रुपये बजट में दिए गए हैं।

### डीडीए के फ्लैटों की डिमांड बढ़ाने का प्रयास

डीडीए के हाउसिंग प्रोजेक्टों में 5310 करोड़ रुपये का रेवेन्यू लगा हुआ है। उम्मीद है कि यूईआर-2, दिल्ली मेट्रो के आने से नरेला के फ्लैट्स की डिमांड बढ़ेगी। इस समय डीडीए द्वारका में 1114 एचआईजी फ्लैट, लोकनायक पुरम में 650 एमआईजी फ्लैट्स और नरेला में 9 हजार एलआईजी व एमआईजी फ्लैट्स बना रहा है। हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए 1767 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसमें 240 करोड़ टीओडी में बन रहे फ्लैट्स के लिए हैं। वहीं इन-सीटू रिहैबिटेशन के तहत 10 नए प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। इसके लिए बजट में 70 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

### स्पोर्ट्स सुविधाओं में किया जाएगा इजाफा

15 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, 3 मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और दो गोल्फ कोर्स के मेंटनेंस के लिए बजट में 178 करोड़ का प्रावधान है। द्वारका सेक्टर-17 मे बन रहे एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का काम लगभग पूरा हो चुका है। द्वारका सेक्टर-8, 19 और 23 में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। एक गोल्फ कोर्स सेक्टर-24 में बन रहा है।

# लैंड यूज़ में बदलाव से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सुधार की उम्मीद

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

**डीडीए की** बोर्ड मीटिंग में राजधानी के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए लैंड यूज में बदलाव किए गए हैं। डीडीए के मुताबिक, जंगपुरा में 33.33 एकड़ जमीन के लैंड यूज को इंडस्ट्रियल और यूटिलिटी से बदलकर ट्रांसपोर्टेशन श्रेणी में किया गया है। नैशनल कैपिटल रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनसीआरटीसी) ने डीडीए से यह अपील की थी। इस जमीन पर आरआरटीएस के तहत यार्ड और स्टेशन के अलावा ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर, एनसीआरटीसी ऑफिस और स्टाफ क्वॉर्टर बनाने हैं। अब इस पर आम लोगों से आपत्तियां और सुझाव मांगे जाएंगे।

> जंगपुरा में 33 एकड़ जमीन को इंडस्ट्रियल और यूटिलिटी से ट्रांसपोर्टेशन श्रेणी में बदलाव

इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रस्तावित सीआरपीएफ ट्रांजिट कैंप के लिए बवाना में 1.94 एकड़ जमीन का लैंड यूज पब्लिक और सेमी पब्लिक से बदलकर रिक्रिएशनल किया गया है। इसके लिए सीआरपीएफ की तरफ से अपील की गई थी।

### नैशनल लॉ यूनिवर्सिटी का विस्तार

**द्वारका** में नैशनल लॉ यूनिवर्सिटी को दो एकड़ अतिरिक्त स्पेस की मंजूरी दी गई है। अथॉरिटी ने यूनिवर्सिटी को टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर, कम्युनिटी हॉल, रिक्रिएशनल हॉल, लाइब्रेरी आदि बनाने के लिए सात एकड़ में से दो एकड़ की मंजूरी दे दी है। इंटीग्रेटेट कॉम्प्लेक्स ऑफ नैशनल लॉ यूनिवर्सिटी इस समय 12 एकड़ जमीन में है। इसके साथ में सात एकड़ जगह हॉस्टल निर्माण के लिए है। अब डीडीए ने इस जगह को दो प्लॉट में बांट दिया है। इसमें दो एकड़ जगह नैशनल लॉ यूनिवर्सिटी को सुविधाएं बढ़ाने के लिए दिए जाने की मंजूरी दी गई है।

**DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY**
**LIBRARY**
**PRESS CLIPPING SERVICE**



# यमुना डूब और हरित क्षेत्र का होगा विकास, सुविधाएं होंगी बेहतर

## डीडीए की बोर्ड बैठक में वर्ष 2023-24 के लिए पारित हुआ 7,643 करोड़ रुपये का बजट, पिछली बार की तुलना में 290 करोड़ रुपये रहा कम

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: उपराज्यपाल व दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के अध्यक्ष वीके सक्सेना की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बोर्ड बैठक में वर्ष 2023-24 के लिए 7,643 करोड़ रुपये का बजट पारित कर दिया गया। इस बार बजट में राष्ट्रीय राजधानी विशेष रूप से नरेला, द्वारका एवं रोहिणी के नागरिक बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने के साथ- साथ ही जी-20 के मद्देनजर यमुना के डूब क्षेत्र, हरित स्थानों के कायाकल्प और बहाली पर विशेष जोर दिया गया है। दिल्ली की तीसरी रिंग रोड (यूईआर टू) को भी प्राथमिकता दी गई है। प्राधिकरण ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए रोहिणी चरण चार और पांच, टिकरी कलां और नरेला के लिए पूर्व-निर्धारित दरों को भी मंजूरी दी। साथ ही सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में सुधार के लिए भू उपयोग परिवर्तन की अनुमति भी दी।

**बजट 290 करोड़ रुपये कम:** प्राधिकरण ने 2023-24 के वार्षिक बजट को 7,643 करोड़ रुपये के वार्षिक परिव्यय के साथ अनुमोदित किया। इस अवधि में डीडीए का राजस्व और प्राप्तियां 8,541 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

मालूम हो कि वर्ष 2022-23 की तुलना में इस बार डीडीए का बजट 290 करोड़ रुपये कम रहा है जबकि इसका राजस्व 598 करोड़ बढ़कर 7,943 की तुलना में 8,541 करोड़ रुपये अनुमानित है।

बजट में रोहिणी और नरेला में खेल परिसरों के लिए खास प्रविधान किए गए हैं। द्वारका में गोल्फ कोर्स बनेगा। बोर्ड बैठक में जंगपुरा में रीजनल रेल ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) प्रतिष्ठानों के लिए भूमि उपयोग के परिवर्तन को भी मंजूरी दी गई। इसके साथ ही बवाना में सीआरपीएफ के ट्रांजिट कैंप के लिए भी स्वीकृति दी गई। एम्स के पुनर्विकास के लिए डीडीए एल एंड डीओ को 219 वर्ग मीटर भूमि भी हस्तांतरित करेगा। बैठक में डीडीए उपाध्यक्ष सुभाशीष पांडा, सदस्य एवं विधायक विजेंद्र गुप्ता, सोमनाथ भारती, ओपी शर्मा व दिलीप पांडे आदि मौजूद रहे।

विकास की राह >> संपादकीय

### बजट में नागरिक सुविधाओं से लेकर पर्यावरण तक का रखा गया ख्याल, विकास में आएगी तेजी

**नागरिक सुविधाएं:** डीडीए के अधिकार क्षेत्र मे आने वाले विकास क्षेत्रो में भूमि के विकास, नागरिक सुविधाओं की बेहतरी और मौजूदा बुनियादी ढाचे के रख- रखाव के लिए 3,314 करोड रुपये का प्रविधान किया गया है। इसमे सड़के, सीवरेज, पानी की आपूर्ति, बिजली की लाइने और जल निकासी शामिल है। ये क्षेत्र मुख्य रूप से नरेला, द्वारका और रोहिणी मे है। डीडीए ने यमुना रिवरफ्रंट के व्यापक विकास की भी योजना बनाई है।

**दिल्ली की तीसरी रिंग रोड के रूप में अर्बन एक्सटेंशन रोड-टू:** (यूईआर-टू) का निर्माण एनएचएआई के माध्यम से प्रगति पर है। इस परियोजना के लिए, कुल परियोजना लागत 6421 करोड़ रुपये (दिल्ली भाग के लिए) मे से 3600 करोड रुपये डीडीए द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा।

- डीडीए ने रोहिणी के विकसित सेक्टर 20, 21 और 22 एव अविकसित सेक्टर 39, 40 और 41 की खाली पडी जमीन तथा आसपास किराडी विधानसभा क्षेत्र मे पानी के जमाव को रोकने के लिए 293.21 करोड़ रुपये की लागत से लगभग 7.2 किमी लबाई के ट्रक ड्रेन के निर्माण की योजना बनाई है। इसके लिए 100 करोड़ रुपये रखे गए हैं।


राज निवास मे डीडीए की बोर्ड बैठक लेते एलजी वीके सक्सेना • सौ. राज निवास

- द्वारका के सेक्टर-8 मे बरसाती नाले का निर्माण कार्य प्रगति पर है। यह नाला हवाई अड्डे के वर्षा जल के अतिरिक्त निर्वहन को पूरा करेगा और द्वारका सेक्टर-8, राजनगर, बगडोला और पालम क्षेत्र मे बाढ़ को रोकेगा। क्षेत्र के घटते जल स्तर को रिचार्ज करने में मदद करने के लिए सेक्टर आठ और सेक्टर 23 द्वारका के पार्कों मे जल निकायो, रिचार्ज पिट्स और जलाशयों का निर्माण करके इस प्रकार छोड़े गए पानी को संग्रहित किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए 30 करोड़ रुपये का प्रविधान है।
- डीडीए ने नेहरू प्लेस और भीकाजी कामा प्लेस वाणिज्यिक केंद्रो की रेट्रोफिटिंग और अपग्रेडेशन का कार्य किया है। मल्टीलेवल कार पार्किंग के निर्माण सहित नवीनीकरण का कार्य प्रगति पर है। इसके लिए 65 करोड रुपये का प्रविधान किया गया है।
- द्वारका मे दो फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके लिए बजट मे छह करोड़ का प्रविधान है।
- कुल परिव्यय 928.92 करोड़ के साथ यमुना नदी के डूब क्षेत्र के कायाकल्प और बहाली का काम किया जा रहा है। 10 अलग-अलग उप परियोजनाओं के रूप में चरणबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। इस उद्देश्य के लिए बजट अनुमान 2023-24 में 405 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है।
- प्रतिष्ठित भारत वंदना पार्क का निर्माण जोरो पर है। सेक्टर-20, द्वारका मे स्थित यह पार्क 189.28 एकड़ मे फैला हुआ है, इसके लिए बजट मे 105 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है।
- डीडीए ने शहर मे हरित स्थानों के समग्र विकास और प्रबंधन, नए पार्कों के विकास, उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए 400 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
- जलाशयों के कायाकल्प के लिए 55 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। आर्द्र भूमि विकसित करने के लिए चार करोड़ का प्रविधान रखा गया है।
- दिल्ली के सभी सात जैव विविधता पार्कों के विकास और रखरखाव के लिए 33 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है।
- दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के लिए 1000 करोड़ देने को प्रतिबद्ध है। इस प्रयोजन के लिए 350 करोड़ का प्रविधान किया गया है।
- डीडीए की बहुमूल्य भूमि के अतिक्रमण को रोकने के लिए भूमि की सुरक्षा/संरक्षा के मद मे 106 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है।

**सात एकड़ में से दो एकड़ पर अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति:** राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय को अपनी सेवाओं का विस्तार करने और अपने छात्रों और कर्मचारियों के लिए व्यापक सुविधाएं प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए, प्राधिकरण ने विश्वविद्यालय को तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र, सामुदायिक हाल स्थापित करने की अनुमति दी है। जो कुछ शर्तों के अधीन कुछ अतिरिक्त गतिविधियों को करने की अनुमति देता है।

**आवास:** डीडीए ने मौजूदा आवास परियोजनाओं की अतिरिक्त सूची की बिक्री के कारण लगभग 4310 करोड़ रुपये के राजस्व का अनुमान लगाया है जो पूरा होने वाला है। उम्मीद है कि एनएच-8 को एनएच-2, नरेला से जोड़ने वाले यूईआर-द्वितीय के पूरा होने और प्रस्तावित मेट्रो लाइन को सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाने की उम्मीद है।

- चालू वर्ष मे पूरी की जाने वाली महत्वपूर्ण आवास परियोजनाओं मे द्वारका गोल्फ कोर्स के सामने लगभग 1114 एचआइजी फ्लैट, लोक नायक पुरम मे लगभग 650 एमआइजी फ्लैट और नरेला मे लगभग 9000 एचआइजी/एमआइजी फ्लैट शामिल हैं। लोक नायक पुरम और नरेला के फ्लैट यूईआर-द्वितीय के करीब हैं जहा काम जोरों पर है।
- कड़कड़डूमा, दिल्ली मे पारगमन उन्मुख विकास (टीओडी) मानदंडों के आधार पर आवासीय परिसरों का निर्माण वर्तमान मे प्रगति पर है। टीओडी मे मेट्रो स्टेशनों, आवासों, कार्यस्थलों और मनोरंजक स्थानों को एक साथ लाना शामिल है। इस परियोजना मे पहले चरण मे 1108 एमआइजी और 522 ईडब्ल्यूएस आवासीय फ्लैटों का निर्माण शामिल है।



- बजट अनुमान 2023-24 मे घरो के निर्माण के लिए कुल 1767 करोड़ रुपये का प्रविधान रखा।

**जेलोरवाला बाग:** 1675 ईडब्ल्यूएस डीयू के डिजाइन और बिल्ड माडल निर्माण के अग्रिम चरण में है और 2023-24 के दौरान पूरा होने की संभावना है।

**कठपुतली कालोनी:** 2800 ईडब्ल्यूएस डीयू का निर्माण पीपीपी माडल पर किया जा रहा है। इसके लिए बजट अनुमान 2023-24 मे 70 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

**खेलकूद को बढ़ावा:** डीडीए के 15 स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स, तीन मिनी स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स और दो गोल्फ कोर्स परिसरों के रख-रखाव के लिए बजट अनुमान 2023-24 में 178 करोड़ रुपये का प्रविधान रखा गया है।

- द्वारका के सेक्टर 17 मे एक स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स का उद्घाटन 2023 की पहली छमाही में और सेक्टर 8, 19 और 23 मे तीन स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स और सेक्टर 24, द्वारका मे एक गोल्फ कोर्स का उद्घाटन भी साल 2023 के अंत तक किया जाएगा।
- डीडीए ने पीपीपी मोड पर द्वारका सेक्टर 19बी मे एक एकीकृत बहु-खेल क्षेत्र का विकास भी किया है। रोहिणी और नरेला मे दो और खेल परिसरों का निर्माण भी पीपीपी मोड पर प्रस्तावित है।
- जगपुरा मे आरआरटीएस के लिए 13.49 हेक्टेयर (33.33 एकड़) क्षेत्र के भूमि उपयोग परिवर्तन को मंजूरी दे दी गई है। यहां स्टेबलिंग यार्ड और स्टेशन, परिचालन नियंत्रण केंद्र, एनसीआरटीसी कार्यालय और स्टाफ क्वार्टर शामिल है। आपत्तियां/सुझाव के लिए सूचना जारी की जाएगी।

**DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY**
**LIBRARY**
**PRESS CLIPPING SERVICE**

NAME OF NEWSPAPERS The Indian Express DATED 30/3/2023

# Sanitation, edu, health push in unified MCD's first budget

**EXPRESS NEWS SERVICE**
NEW DELHI, MARCH 29

THE MUNICIPAL Corporation of Delhi Wednesday passed the budget for the 2023-24 financial year, with a focus on improving sanitation, cleanliness, education, health, welfare of workers, traders and reducing the three garbage mountains.

Passing the Rs 16,203-crore budget, MCD Mayor Shelly Oberoi said: "This is the first budget of the deliberative wing of the unified MCD. We owe it to the people of Delhi to give them a fully functioning MCD. Our aim is to make this civic body the number one in the country."

The revised budget estimate for the current fiscal, Rs 14,804 crore (expenditure), was also passed. Under the budget, the civic body has allocated land in Tehkhand for constructing engineering landfill sites. Land measuring 47.346 acres was allotted by the DDA in Tehkhand near Okhla, and the engineering landfill site will be set up on 32.34 acres of the total land. Work to set up this site is expected to be completed by April. One of the AAP's MCD poll promises was to clear the landfills.

The budget has also proposed to install CCTVs in 570 school locations and plant 1.5 lakh saplings ahead of the G-20 Summit.

In the special budget meeting, 17 resolutions were placed by the AAP and BJP. The House passed all resolutions tabled by the AAP, those placed by the BJP were rejected.

**The Rs 16,203 crore civic budget was passed by the first mayor of the unified MCD, Shelly Oberoi.** *Tashi Tobgyal*

The meeting, which saw Deputy Mayor Aaley Mohammad Iqbal and BJP councillors Kamaljeet and Shikha Rai present their views, saw arguments from both sides. While AAP hit out at BJP for misusing the MCD during its 15-year rule, the latter levelled allegations of corruption by AAP over the incarceration of its two leaders — Satyender Jain and Manish Sisodia.

Attacking the BJP, Aaley cited a dialogue from the movie Pathaan and said, "'*Aap Apni kursi ki peti baand lijiye, mausam bigadne wala hai*'... but I want to tell the people of Delhi that now they can relax kyunki *ab mausam acha rahega MCD mein*."

Later in a press conference, AAP MCD in-charge Durgesh Pathak said the government had promised 10 guarantees and it has fulfilled two of them in 36 days – MCD employees will receive their salaries on time and traders will get relief from sealing.

Meanwhile, L-G V K Saxena approved the DDA's annual budget. The key focus this year will be on civic infrastructure, rejuvenation of Yamuna floodplains, development of green spaces in the capital, and in-situ rehabilitation of slum dwellers.

Special emphasis on the third Ring Road (UER-II) for Delhi and development of Narela, Dwarka and Rohini, and sports complexes in Rohini and Narela have also been proposed. The authority also approved change of land use for RRTS installations in Jangpura, a transit camp for CRPF at Bawana, and transfer of 219 sq m of land to L&DO for amalgamation aimed at redevelopment of AIIMS.

**DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY**
**LIBRARY**
**PRESS CLIPPING SERVICE**

WWW.INDIANEXPRESS.COM
NAME OF NEWSPAPER: **THE INDIAN EXPRESS,** THURSDAY, MARCH 30, 2023

# Attempt to do away with construction restrictions in morphological ridge: SC panel raises apprehension

**ABHINAYA HARIGOVIND**
NEW DELHI, MARCH 29

THE CENTRAL Empowered Committee (CEC) of the Supreme Court has expressed the "apprehension" of a "well-coordinated attempt to do away with the restrictions on the construction activities in morphological ridge".

The morphological ridge is the area that has ridge-like features typical of the Aravallis and has ecological significance but lies outside the notified ridge forest land. The Delhi Forest Department says that the morphological ridge should work as a buffer zone to protect the "core forest area of the ridge" and that the morphological ridge area is a "high-risk zone", making the construction of high-rise buildings dangerous. Construction in the area requires clearance from the Ridge Management Board and the CEC.

**The morphological ridge is the area that has ecological significance but lies outside notified ridge forest land**

The Committee made the remarks in a report submitted to SC.

Delhi Development Authority (DDA), which is the land-owning agency, said in an affidavit to the SC that the restrictions on use of morphological ridge land are without "legal sanction". The CEC countered this and a committee appointed on the orders of the Supreme Court is now in the process of identifying the area of the morphological ridge.

The matter came up before the CEC and the Supreme Court when the DDA allotted land on the morphological ridge in Vasant Kunj to the Directorate of Revenue Intelligence (DRI) to construct an office building.

In a February 8 order, the SC noted that previous orders passed by courts had said that land with similar features as the Ridge should be given the same protection. The SC had then directed that a committee be constituted to identify such areas.

It had also directed that the DDA should not allot any land in the areas which are under this consideration till further orders.

The CEC's report says that the area occupied by the geomorphological landform in a fresh map layer has come down to 1,1050.92 hectares from 1,1136.23 hectares mapped in 2013, which includes the notified forest of the ridge and the morphological ridge. The CEC in its report recommended that the SC direct the committee appointed by it to follow the boundaries shown in the 2013 map.

The CEC report also said that in an affidavit before SC in February, DDA said that the morphological ridge has not been defined under any statute, notification, or policy for it to attain legal sanctity. "Even though the map of Geomorphological Ridge has been available since 2013, DDA has now taken the stand before this Hon'ble Court that the Ridge outside the Notified Ridge Area has not been identified / demarcated," the CEC report said.

The report also noted that the Master Plan of Delhi 2021 does not recognise any part of the ridge outside of the notified forest area.

The report added that DDA had allotted plots for development to various agencies in the morphological ridge.

After the CEC submitted its report dated March 13, the SC considered the matter earlier this month. In an order issued on March 15, it said the committee has made "substantial progress" and has identified the parameters to be considered to identify land as morphological ridge. Another committee of technical experts will be appointed and the matter is to be considered by the court in four months to monitor progress.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS नई दिल्ली, 31 मार्च, 2023 दैनिक जागरण ATED----------

# निगम की अनुमति के बिना सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद में किया जा रहा था निर्माण

## निगम ने लगाई हुई है रोक, हिंदू संगठन अखंड भारत मोर्चा ने की थी प्रशासन से शिकायत

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली : गाजीपुर लैंडफिल साइट के पास सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद परिसर में निगम की अनुमति के बिना धड़ल्ले से नया निर्माण कार्य किया जा रहा था। दीवारों के साथ ही पिलर खड़े कर दिए गए थे। एसडीएम के आदेश के बाद फिलहाल काम बंद है। लोगों का आरोप है कि जिस वक्त निर्माण कार्य किया जा रहा था, तब दिल्ली निगम ने आंखें बंद की हुई थीं।

मस्जिद कमेटी का कहना है कि कूड़े का पहाड़ गिरने से मस्जिद का काफी हिस्सा टूट गया था, उसे ठीक किया जा रहा है, जबकि हिंदू संगठन अखंड भारत मोर्चा का कहना है कि सरकारी जमीन को घेरकर अवैध निर्माण किया जा रहा था। जिस वक्त निर्माण कार्य हो रहा था, तब किसी भी विभाग ने सुध नहीं ली। इस मामले में निगम के एक अधिकारी ने बताया कि यह जमीन निगम के अधीन नहीं है। यह जमीन दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की है, यहां पर कोई गतिविधि होती है तो उस पर कार्रवाई वहीं विभाग कर सकता है।

गाजीपुर लैंडफिल साइट के पास सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद के परिसर में बंद पड़ा निर्माण कार्य • जागरण

जमीन किस विभाग की है इसके बारे में अभी पता नहीं है। दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली आश्रय सुधार बोर्ड को पत्र लिखकर पता किया गया है, अभी किसी विभाग ने अपना जवाब नहीं दिया है। धार्मिक स्थल के परिसर में निर्माण कार्य पर रोक लगी है। उस जगह पर कोई निर्माण कार्य नहीं करा सकता है - संदीप दता, उपजिलाधिकारी, मयूर विहार

मस्जिद कमेटी के सदस्य जाहिद ने बताया कि मस्जिद लैंडफिल साइड के करीब है। नई मस्जिद नहीं बनाई जा रही, बल्कि परिसर में ही निर्माण कार्य किया जा रहा था। नवंबर 2022 में गाजीपुर लैंडफिल साइट का कुछ हिस्सा अचानक से गिर गया था, जिससे बकरा मंडी की दीवार व मस्जिद का काफी हिस्सा टूट गया था। उस वक्त मंडी की दीवार निगम ने बनवा दी थी। मस्जिद की दीवार व बाकी जो हिस्सा टूटा था, उसे नहीं बनाया गया था। मस्जिद का जितना हिस्सा टूटा था, उसे बनाया जा रहा था।

**डीडीए के नक्शे में हैं मंदिर व मस्जिद**

**: प्रधान:** गाजीपुर डेयरी फार्म फार्मर एसोसिएशन के प्रधान संतराम ने कहा कि 1976 में डीडीए ने गाजीपुर डेयरी फार्म को बसाया था। कुछ समय के बाद डीडीए ने उस जमीन को दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड को सौंप दिया था। डीडीए ने 2200-2200 गज जमीन मंदिर व मस्जिद को दी थी। डेयरी फार्म में बसे सभी धर्म व जाति के लोगों ने चंदा जमा करके दोनों धार्मिक स्थलों का निर्माण कार्य करवाया था। बकायदा डीडीए के नक्शे में भी दोनों धार्मिक स्थलों का जिक्र है। यह झूठ है कि सरकारी जमीन पर कब्जा हो रहा है।